



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 अक्टूबर, 1984/28 अगस्त, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 सितंबर, 1984

संख्या राजस्व-2क(3)4/76.—हिमाचल प्रदेश विपदग्रस्त (ऋण सुविधा) नियम, 1984 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश विपदग्रस्त व्यक्ति (ऋण सुविधा) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 6 की अपेक्षानुसार अधिसूचना सं० राजस्व 2क(3)4/76, तारीख 23 सितम्बर, 1983 के अन्तर्गत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में, तारीख 21 जनवरी, 1984 को प्रकाशित किया गया था, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके सबसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और नियत तिथि अवधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विपदग्रस्त व्यक्ति (ऋण सुविधा) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

### हिमाचल प्रदेश विपदग्रस्त व्यक्ति (ऋण सुविधा) नियम, 1984

#### प्रथम अध्याय

#### प्राथमिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश विपदग्रस्त व्यक्ति (ऋण सुविधा) नियम, 1984 कहे जा सकते हैं।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश विपदग्रस्त व्यक्ति (ऋण सुविधा) अधिनियम, 1976 (1976 का 18) अभिप्रेत है ;

(ख) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से नियम 3 के अधीन विपदग्रस्त व्यक्ति को प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई सीमा तक ऋण स्वीकृत करने हेतु सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) “विपदग्रस्त व्यक्ति” अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित प्राकृतिक या अन्य विपत्तियों द्वारा कारित विपदा से प्रभावित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) “प्रारूप” से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(च) “तहसीलदार” से सरकार द्वारा तत्समय उस रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें उप-तहसील का नायब-तहसीलदार भी सम्मिलित है।

#### अध्याय 2

#### विपदग्रस्त व्यक्ति को ऋण स्वीकृति

3. ऋण की स्वीकृति.—राज्य सरकार या इसमें नीचे उल्लिखित अन्य प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है) प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई सीमा तक, विपदग्रस्त व्यक्ति को ऋण स्वीकृति कर सकता है :—

(1) बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन, अग्नि और अतिवृष्टि के कारण हुई विपदा की अवस्था में :—  
(क) गृह या दुकान के निर्माण के लिए :—

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. जिलाधीश     | 10,000 रुपये तक  |
| 2. मण्डलायुक्त | 10,000 रुपये से अधिक परन्तु 15,000 रुपये से अधिक नहीं। |
| 3. वित्तायुक्त | 15,000 रुपये से अधिक परन्तु 20,000 रुपये से अधिक नहीं। |
| 4. राज्य सरकार | 20,000 रुपये से अधिक कोई भी राशि।                      |

(ख) गृह या दुकान की मरम्मत के लिए :—

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) | 1,000 रुपये तक  |
| (2) जिलाधीश                 | 5,000 रुपये तक  |
| (3) मण्डलायुक्त             | 5,000 रुपये से अधिक परन्तु 10,000 रुपये से अधिक नहीं। |

(4) वित्तीय 10,000 रुपये से अधिक कोई भी राशि।

(ग) भूमि सुधार या क्रय करने के लिए:—

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) जिलाधीश     | 5,000 रुपये तक।  |
| (2) मण्डलायुक्त | 5,000 रुपये से अधिक परन्तु 15,000 रुपये से अधिक नहीं।  |
| (3) वित्तीय     | 15,000 रुपये से अधिक परन्तु 25,000 रुपये से अधिक नहीं। |

(घ) किसी अन्य प्रयोजन के लिए:—

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) | 1,000 रुपये तक।                                      |
| (2) जिलाधीश                 | 1,000 रुपये से अधिक परन्तु 5,000 रुपये से अधिक नहीं। |

(2) अकाल, हिम-तुफान, ओलावृष्टि, अत्याधिक अनावृष्टि, आधी या टिड्डी दल के कारण हुई विपदा की अवस्था में:—

(क) पशु क्रय करने के लिए:—

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) | 1,000 रुपये तक।                                      |
| (2) जिलाधीश                 | 1,000 रुपये से अधिक परन्तु 3,000 रुपये से अधिक नहीं। |

(ख) किसी अन्य प्रयोजन के लिए:—

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) तहसीलदार              | 200 रुपये तक।                                      |
| (2) उप-मण्डलाधिकारी (सि०) | 200 रुपये से अधिक परन्तु 500 रुपये से अधिक नहीं।   |
| (3) जिलाधीश               | 500 रुपये से अधिक परन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं। |

(3) बज्रपात या विद्युत घात से हुई विपदा की अवस्था में:—

(क) पशु क्रय करने के लिए:—

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) | 1,000 रुपये तक।                                      |
| (2) जिलाधीश                 | 1,000 रुपये से अधिक परन्तु 3,000 रुपये से अधिक नहीं। |

(ख) किसी अन्य प्रयोजन के लिए:—

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) उपमण्डलाधिकारी (सि०) | 1,000 रुपये तक।                                       |
| (2) जिलाधीश              | 1,000 से अधिक परन्तु 5,000 रुपये से अधिक नहीं।        |
| (3) मण्डलायुक्त          | 5,000 रुपये से अधिक परन्तु 15,000 रुपये से अधिक नहीं। |

(4) किसी महामारी द्वारा हुई विपदा की अवस्था में:—

जैसा सम्बन्धित विभाग द्वारा विहित किया जाए।

4. आवेदन का प्रारूप:—इन नियमों के अधीन ऋण की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र प्रारूप-1 में सम्पन्न रूप से हस्ताक्षरित और मूल अनुलिपि से चिह्नित दो प्रतियों में सम्बन्धित तहसीलदार को दिया जायगा।

5. सत्यापन.—आवेदन पत्र प्राप्त करने पर तहसीलदार समुचित जांच पड़ताल करेगा और अपनी रिपोर्ट और सिफारिशों सहित (जिन्हें पृथक कागज पर अभिलिखित और "गोपनीय" से अंकित किया जायेगा) प्रारूप की एक प्रति सक्षम अधिकारी को शीघ्र ही, और यदि आवेदित ऋण को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, मण्डलायुक्त, वित्तायुक्त या राज्य सरकार हो तो, उपायुक्त के माध्यम से आदेशार्थ भेजेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी के आदेश.—(1) सक्षम प्राधिकारी जिसे नियम 5 के अधीन आवेदन पत्र भेजा गया है वह देखेगा कि आवेदित ऋण की राशि प्रारूप में यथा उपदर्शित पुनर्वास प्रयोजन के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है और क्या निवेदन वास्तविक है और ऐसे सभी तथ्यों के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के उपरांत वह:

(क) आवेदन पत्र को अस्वीकार कर सकता है, या

(ख) यदि उसका ऐसा समाधान हो जाता है कि आवेदित ऋण की राशि घोषित प्रयोजन के लिए अत्यधिक है तो ऋण की राशि को उस सीमा तक कम कर सकता है जिस तक वह आवेदन पत्र में उपदर्शित प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझता हो और आवेदन को संगत पत्रों सहित उचित निर्देशों के साथ कम की गई राशि को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वापिस भेज सकता है। ऐसे मामलों में निम्न प्राधिकारी को दिया गया निर्देश नियम 5 के अधीन किया गया निर्देश समझा जायेगा, या

(ग) आवेदित ऋण को स्वीकार कर सकता है :

परन्तु आवेदक को मौखिक रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किए बिना कोई भी आवेदन पत्र अस्वीकार नहीं किया जायेगा या ऋण की किसी भी राशि में कमी नहीं की जायेगी और सक्षम प्राधिकारी अस्वीकार करने या राशि को कम करने के कारणों को लिखित रूप से अभिलिखित करेगा, परन्तु सक्षम प्राधिकारी प्रारूप पर स्वयं आदेश अभिलिखित करेगा, जिसे, यथा स्थिति ऋण की राशि सहित या रहित तहसीलदार को वापिस भेजा जायेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी ऋण को स्वीकृत करने निर्णय लेता है तो वह उन किस्तों की संख्या जिनमें ऋण वापिस किया जायेगा, ऋण पर प्रभार्य व्याज दर और ऋण किस्तों की देय तिथियों के विषय में स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी धारा 5 के प्रयोजन के लिए राशि के उस प्रभाग को दर्शाते हुए एक विवरण तैयार करेगा जिसका प्रत्येक विपद्ग्रस्त व्यक्ति द्वारा अभिदाय किया जाना है यदि ऋण दो या अधिक विपद्ग्रस्त व्यक्तियों को एक ही संयुक्त आवेदन पत्र पर स्वीकृत किया गया है।

7. ऋण का संवितरण—(1) नियम 8 के अधीन ऋण को स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत की गई राशि को विपद्ग्रस्त व्यक्ति को संदाय करने के लिए तहसीलदार को भेज देगा।

(2) आदेशों या ऋण राशि के प्राप्त करने पर तहसीलदार नियम 5 के अधीन उस द्वारा रखी गई प्रारूप की दूसरी प्रति पर समुचित टिप्पणी अभिलिखित करेगा, और

(क) विपद्ग्रस्त व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के सम्बन्ध में सूचना देगा, या

(ख) यथास्थिति, प्रारूप में उल्लिखित आङ्मान पर यदि ऋणी के पास कुछ भी आङ्मान करने के लिए नहीं है तो प्रतिभू प्राप्त करने के उपरांत उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त की गई राशि का विसर्गस्त व्यक्ति को प्रदान कर देगा।

8. दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त आवेदन पत्र.—यदि दो या अधिक विपद्ग्रस्त व्यक्ति इन नियमों के अधीन संयुक्त रूप से ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र प्रारूप-1 में ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम उपदर्शित करते हुए संयुक्त रूप में दिया जायेगा और यह एक या सभी आवेदकों द्वारा तहसीलदार को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र को पूर्ववर्ती नियमों में अन्य मामलों के लिए फिर विहित रीति के अनुसार ही संब्यहृत किया जायेगा :

परन्तु जहाँ इस नियम के अधीन ऋण स्वीकृत किया जाता है तो राशि का संयुक्त रूप से आवेदकों को जब वे सभी उपस्थित हो संदाय किया जायेगा और वे संयुक्त एवं पृथक रूप से उस प्रकार दी गई राशि के प्रति संदाय के लिए राज्य सरकार को आबद्ध होंगे ।

### अध्याय 3

#### प्रभार्य व्याज दर और ऋण की प्रतिभूति

9. व्याज की दर—(1) इन नियमों के अधीन स्वीकृत किए गए ऋणों पर प्रभार्य व्याज, राज्य सहकारी बैंक द्वारा मंजूर किए गए ऋणों के लिए निहित की गई दर पर साधारण व्याज होगा ।

(2) व्याज ऋण के संवितरण की तारीख से प्रभार्य होगा ।

10. प्रतिभूति—(1) यथा स्थिति विपदग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों को ऋण का संवितरण करने से पूर्व तहसीलदार नियम 7 के अनुसरण में यथा स्थिति प्रतिभूतियों से आवेदन पत्र पर उचित आङ्मान या हस्ताक्षर और अन्य विवरण प्राप्त करेगा और उससे द्वारा आगे कार्यालय में रखी गई प्राप्ता को दूसरी प्रति पर इस की विस्तृत टिप्पणी अंकित करने के उपरांत इसे सक्षम प्राधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेज देगा ।

(2) तहसीलदार उनकी प्रस्थापना को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभू के रूप में अपनी प्रस्थापना करने वाले व्यक्तिगण इतनी अचल सम्पत्ति धारण करते हों कि उससे स्वीकृत ऋण की राशि और उस पर प्रभार्य व्याज की पूर्ति की जा सके ।

(3) अपने आप को प्रतिभू के रूप में प्रस्थापित करने वाले व्यक्ति ऋण की राशि और उस पर के व्याज के प्रतिसंदाय के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से सरकार को आबद्ध होंगे ।

### अध्याय 4

#### ऋण की वसूली

11. तारीख जिससे ऋण की वसूली देय होगी और किश्तों की संख्या—इन नियमों के अधीन स्वीकृत किया गया प्रत्येक ऋण बीस से अल्पतः छमाही किश्तों में वसूल किया जायेगा और ऐसी प्रथम किश्त नियम 7(2) (ख) के अधीन संदाय करने की तारीख से 18 मास की अवधि के पश्चात् प्रारम्भ होगी ।

(2) ऋण की पूरी वसूली हो जाने के पश्चात्, ऋणी से वसूल किये जाने वाले व्याज की राशि को गणना नियम 9 के अधीन विहित की गई दर पर की जायेगी और छः से अल्पतः मासिक किश्तों में वसूल की जायेगी और यह उस मास के ठीक पश्चात्वर्ती मास से, जिसमें ऋणों की अन्तिम किश्त वसूल की गई थी, प्रारम्भ होगी ।

12. संयुक्त आवेदन पत्र की अवस्था में ऋणियों और प्रतिभूगण को उनसे दायित्व के सम्बन्ध में सूचित करना जहाँ ऋण दो या दो से अधिक विपदग्रस्त व्यक्तियों को संयुक्त आवेदन पत्र पर स्वीकृत किया गया हो, तहसीलदार पारस्परिक ऋणों के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति और प्रतिभू की राशि के उस संभाग के सम्बन्ध में जिसका प्रत्येक को नियम 6 के दूसरे परन्तुक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों के अधीन और प्रतिभू के रूप में संविदाय करना है, स्थिति स्पष्ट है करेगा ।

## अध्याय 5

## प्रकीर्ण

13. ऋण के वास्तविक प्रयोजन के लिए किये गये उपयोग का सत्यापन ऋण को वसूली के प्रारम्भ होने के पश्चात्, ब्याशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी यह मानने के लिए, कि क्या विपदग्रस्त, व्यक्ति को संदाय की गई ऋण राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके वह स्वीकृत की गई थी, जांच करेगा या करवायेगा और परिणाम की तहसीलदार को सूचना देगा।

14. ऋण के दुरुपयोग करने पर ऋण की राशि का एक मुश्त वसूल करना.—यदि नियम 13 के अधीन की गई जांच से यह पता चले कि विपदग्रस्त, व्यक्ति को स्वीकृत की गई ऋण की राशि का उसी, प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, तो सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी, यह आदेश पारित करेगा कि नियम 9 के अधीन संगणित ब्याज सहित ऋण की शेष राशि, और 5 प्रतिशत की दर से शस्तिक ब्याज और खर्च यदि हो, भूराजस्व के बकाया के रूप में तुरन्त एक मुश्त वसूल किये जाए।

15. ऋणियों का अभिलेख.—इन नियमों के अधीन स्वीकृत किये गये प्रत्येक ऋण का विवरण दिखाने वाला एक रजिस्टर तहसीलदार द्वारा प्रारूप-2 में तैयार किया जायेगा और लेखा परीक्षा विभाग द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

## प्रारूप-1

## (नियम 4 देखें)

1. आवेदक (आवेदकों) का नाम, पिता का नाम और पूरा पता।
2. विपदा का स्वरूप जिससे प्रभावित हुआ है।
3. हानि की सीमा।
4. वह स्थान जहां हानि हुई है।
5. आवेदित ऋण राशि।
6. प्रयोजन जिसके लिए ऋण अपेक्षित है, अर्थात् वे पग जिन्हें आवेदक अपने पुनर्वास के लिए ऋण की सहायता से उठाने का विचार रखता है।
7. वह स्थान जहां आवेदक स्तम्भ 6 में बताए गए पगों पर ऋण की राशि का उपयोग करना चाहता है।
8. आवेदक को उस अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण और भू-अभिलेख में उस की स्थिति, जिसे वह बन्धक रखना चाहता है।

आवेदक के हस्ताक्षर।

सक्षम प्राधिकारी के आदेश।

सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय की मोहर, सहित हस्ताक्षर।

(ऋण के स्वीकृत हो जाने के उपांतरण तहसीलदार के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

अदायगी प्राप्त की।

मैंने या हमने, मुझ या हमें हिमाचल प्रदेश विपद्ग्रस्त व्यक्ति (ऋण सुविधा) नियम, 1984 को पढ़ लिया है/ समझाया गया है और मैं या हम इन नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ या देते हैं।

ऋणी के हस्ताक्षर।

मैंने या हमने या मुझे या हमें उपर्युक्त नियम पढ़ लिए हैं या समझा दिये गये हैं और अपनी जिम्मेदारी या दायित्व को अच्छी तरह समझ लेने के बाद यह वचन देता हूँ या देते हैं कि यदि उपर्युक्त ऋणी ऋण लौटाने में असमर्थ रहता है तो मैं या हम सरकार का ब्याज और अन्य खर्चें सहित, यदि कोई हो ऋण लौटाऊंगा या लौटाएँगे।

प्रतिभू 1.

प्रतिभू 2.

(यहाँ प्रतिभू का पूरे पते सहित पूर्ण विवरण दें)।

#### प्रास्ता-2

(नियम 15 देखें)

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम और पूरा पता।
2. विपदा का स्वरूप जिससे प्रभावित हुआ है।
3. हानि की सीमा।
4. वह स्थान जहाँ हानि हुई।
5. स्वीकृत हुई ऋण राशि और आदेशों का विवरण (संख्या और दिनांक सहित)।
6. प्रयोजन जिसके लिए ऋण स्वीकृत हुआ है अर्थात् वह पग जिन्हें आवेदक अपने पुनर्वास के लिए ऋण की सहायता से उठाने का विचार रखता है।
7. आवेदक को स्वीकृत किये गये ऋण का प्रतिभूति के लिए सरकार के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण।
8. (क) नियम 6 के दूसरे परन्तुक के अनुसार ऋण की वसूली प्रारम्भ होने की तारीख।  
(ख) किस्तों की निर्धारित संख्या।  
(ग) प्रत्येक किस्त की राशि।  
(घ) ब्याज दर।
9. वसूली की प्रगति (अर्थात् किस्तों की वसूली की तारीख और चालान की संख्या एवं तारीख जिसके द्वारा किस्त जमा की गई)।
10. नियम 13 के अधीन हुए निरीक्षण का परिणाम।
11. नियम 14 के अधीन आदेश, यदि कोई हो और उनका परिणाम (अर्थात् उन पर की गई कार्यवाही)।
12. पिछली किस्त और ब्याज की वसूली की तारीख।
13. तहसीलदार के हस्ताक्षर।

आदेश द्वारा;  
अक्षर सिंह,  
सचिव (राजस्व),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

*Authoritative English text of Notification No. Rev. 2A (2)-4/76, dated 1-9-84 is hereby published as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.*

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 1st September, 1984*

**No. Rev. 2A (3)-4/76.**—Whereas the draft rules entitled the Himachal Pradesh Distressed Persons (Facilities for Loans) Rules, 1984, were published, as required under section 6 of the Himachal Pradesh Distressed Persons (Facilities for Loans) Act, 1976 (Act No. 18 of 1976), in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extraordinary), dated the 21st January, 1984, *vide* Notification No. Rev. 2A (3)-4/76, dated the 23rd September, 1983 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby;

AND WHEREAS no objection or suggestions were received within the stipulated period.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Himachal Pradesh Distressed Persons (Facilities for Loans) Act, 1976 (Act No. 18 of 1976), the Governor, Himachal Pradesh hereby makes the following rules:—

## THE HIMACHAL PRADESH DISTRESSED PERSONS (FACILITIES FOR LOANS) RULES, 1984

### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Distressed Persons (Facilities for Loans) Rules, 1984.

(2) These shall come into force at once.

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Distressed Persons (Facilities for Loans) Act, 1976 (18 of 1976);

(b) “section” means a section of the Act;

(c) “competent authority” or “authority competent” means an authority empowered to grant loans under rule 3 to a distressed person, to the extent shown against each;

(d) “distressed (s)” means a person affected by distress caused by natural or other calamities mentioned in section 3 of the Act;

(e) “form” means a form appended to these rules; and

(f) “tehsildar” means an officer appointed as such by the Government for the time being and includes a Naib-Tehsildar of a Sub-Tehsil.



## CHAPTER II

### GRANT OF LOAN TO DISTRESSED PERSON

3. *Grant of loan.*—The State Government or other authority (hereinafter referred to as the competent authority) mentioned hereunder, may grant loan to a distressed person to the extent specified against each.

#### (1) IN THE CASE OF DISTRESS CAUSED BY FLOODS, EARTHQUAKES, LANDSLIDES, AVALANCHES, FIRE AND EXCESSIVE RAINS:—

##### (a) For construction of house or a shop:—

(i) Deputy Commissioner

(ii) Div. Commissioner

Upto Rs. 10,000.

Upto an amount exceeding Rs. 10,000 but not exceeding Rs. 15,000.

An amount exceeding Rs. 15,000 but not exceeding Rs. 20,000.

Any amount exceeding Rs. 20,000.

(iii) Financial Commissioner

(iv) State Government

##### (b) For repair of a house or a shop:—

(i) S.D.O. (C)

(ii) D.C.

Upto Rs. 1,000.

Upto Rs. 5,000.

An amount exceeding Rs. 5,000 but not exceeding Rs. 10,000.

Any amount exceeding Rs. 10,000.

(iv) Financial Commissioner

##### (c) For improvement of purchase of land:—

(i) Deputy Commissioner

(ii) Div. Commissioner

Upto Rs. 5,000.

An amount exceeding Rs. 5,000 but not exceeding Rs. 15,000.

An amount exceeding Rs. 15,000 but not exceeding Rs. 25,000.

(iii) Financial Commissioner

##### (d) For any other purpose:—

(i) S.D.O. (C)

Upto Rs. 1,000.

An amount exceeding Rs. 1,000 but not exceeding Rs. 5,000.

(ii) Deputy Commissioner

#### (2) IN THE CASE OF DISTRESS CAUSED BY FAMINE, SNOW STORM, HAIL STORM SEVERE DROUGHT, WIND STORM OR LOCUST:—

##### (a) For purchase of cattle:—

(i) S.D.O. (C)

Upto Rs. 1,000.

An amount exceeding Rs. 1,000 but not exceeding Rs. 3,000.

(ii) Deputy Commissioner

##### (b) Any other purpose:—

(i) Tehsildar

(ii) S.D.O. (C)

Upto Rs. 200.

An amount exceeding Rs. 200 but not exceeding Rs. 500.

An amount exceeding Rs. 500 but not exceeding Rs. 1,000.

(iii) Deputy Commissioner

#### (3) IN THE CASE OF DISTRESS CAUSED BY LIGHTNING OR ELECTRIC SHOCK:—

##### (a) For purchase of cattle:—

(i) S.D.O. (C)

Upto Rs. 1,000.

An amount exceeding Rs. 1,000 but not exceeding Rs. 3,000.

(ii) Deputy Commissioner

##### (b) For any other purpose:—

(i) S.D.O. (C)

Upto Rs. 1,000.

An amount exceeding Rs. 1,000 but not exceeding Rs. 5,000.

An amount Rs. 5,000 but not exceeding Rs. 15,000.

(ii) Deputy Commissioner

(iii) Div. Commissioner

## (4) IN CASE OF DISTRESS CAUSED BY AN EPIDEMIC:—

As prescribed by department concerned.

4. *Form of Application.*—An application for the grant of loans under these rules shall be submitted to the Tehsildar concerned in duplicate, in Form-I duly signed and marked as "Original" and "Duplicate".

5. *Verification.*—The Tehsildar on receipt of application shall make appropriate enquiry and forward one copy of the form, with a report and his recommendations (to be recorded on separate sheet and marked confidential) for orders, to the competent authority direct and who the authority competent to sanction the loan applied for is the Divisional Commissioner, Finance Commissioner or the State Government, through the Deputy Commissioner concerned.

6. *Orders of the Competent Authority.*—(1) The competent authority to whom the application has been forwarded under rule 5, shall consider whether the amount of loan applied for represents the minimum requirement for the purpose of rehabilitation as indicated in the form, and whether the request is genuine and, after satisfying itself about all such factors, may:—

- (a) reject the application; or
- (b) reduce the amount of loan to the extent which it considers sufficient for the purpose indicated in the application if it is satisfied that the amount of the loan applied for is excessive for the declared purpose, and return the application with all relevant papers to the authority competent to sanction the reduced amount of loan with such directions. In such a case, a reference to the lower authority shall be deemed to be a reference made under rule 5; or
- (c) sanction the loan applied for:

Provided that no application shall be rejected or the amount of loan shall be reduced without affording the applicant an opportunity to explain his case either in writing or orally and the competent authority shall record the reasons for rejection or reduction of amount in writing.

Provided further that the competent authority shall record the orders on the form itself, which shall be returned to the Tehsildar, with or without the amount of loan, as the case may be. In case the competent authority decides to sanction the loan, it shall clearly, pass orders as to the number of instalments in which the loan shall be refundable, the rate of interest chargeable on the loan and the due date(s) for the repayment of instalments of loan.

(2) The competent authority shall, for the purposes of section 5, also prepare a statement showing the portion of the amount of loan which as among themselves each of the distressed person is bound to contribute, in case the loan is granted to two or more distressed persons on a joint application.

7. *Disbursement of loan.*—(1) After sanctioning the loan under rule 6, the competent authority shall send the amount of loan sanctioned to the Tehsildar for payment to the distressed person.

(2) On the receipt of orders or the amount of the loan, the Tehsildar shall record an appropriate note on the other copy of the form retained by him under rule 5; and—

- (a) inform the distressed person of the orders of the competent authority; or
- (b) make payment of the amount received under sub-rule (1), to the distressed person after obtaining proper hypothecation or if the loanee has nothing to hypothecate, surety as mentioned in the form of application, as the case may be.

8. *Joint application by two or more distressed persons.*—(1) Where two or more distressed persons apply for a loan under these rules jointly, the application shall be made jointly in Form-I indicating therein the names of all such persons and it may be presented to the Tehsildar by all or any of the applicants, in duplicate.

(2) The application shall be processed in the same manner as prescribed for the other cases in the preceding rules:

Provided that where a loan is sanctioned under this rule, the amount shall be paid to the applicants jointly, when all of them are present and all of them shall be jointly and severally bound to the State Government for the repayment of the whole amount payable in respect thereof.

### CHAPTER III

#### RATE OF INTEREST TO BE CHARGED AND SECURITY OF LOANS

9. *Rates of Interest.*—(1) The interest to be charged on the loans granted under these rules shall be simple interest at the rates prescribed by the State Co-operative Bank for loans granted by it.

(2) The interest shall be chargeable with effect from the date of disbursement of the loan.

10. *Sureties.*—(1) Before the loan is disbursed to the distressed person or persons as the case may be, the Tehsildar shall obtain proper hypothecation or the signatures and other particulars of the sureties on the application form as the case may be, in term of rule 7 and forward it to the competent authority for safe custody after making a detailed note of it on the other copy of the form retained by him in his office.

(2) The Tehsildar shall ensure that the persons offering themselves as sureties possess immovable property sufficient to make good the amount of loan sanctioned together with the interest chargeable thereon, before he accepts their offer.

(3) The persons offering themselves as sureties shall be jointly and severally bound to the State Government for the repayment of the amount of loan and the interest thereon.

### CHAPTER IV

#### RECOVERY OF LOANS

11. *Date from which the recovery shall become due and the number of instalments.*—(1) Every loan granted under these rules shall be recoverable in half-yearly instalments, not exceeding twenty the first of such instalments commencing after a period of 18 months from the date of payment under rule 7 (2) (b).

(2) After the loan has been recovered in full, the amount of interest recoverable from the loanee, shall be calculated at the rate prescribed under rule 9 and recovered in monthly instalments not exceeding six, commencing from the month following the month in which the last instalment of loan was recovered.

12. *Loanee and sureties to be informed of their liability in case of joint application.*—Where loan is granted to two or more distressed persons on a joint application, the Tehsildar shall explain to each such person and surety the portion of the amount which each of them is bound to contribute as amount themselves as a loanee in terms of the orders passed by the competent authority under second proviso to rule 6, and, as a surety.

## CHAPTER V

## MISCELLANEOUS

13. *Verification as to the utilisation of loan on the bona fide purpose.*—As soon as may be after the recovery of the loan commences, the competent authority shall make or cause to be made enquiries to find out as to whether the amount of loan paid to a distressed person, has been utilised for the purpose for which it has been sanctioned and intimate the result to the Tehsildar concerned.

14. *Amount of loan to be recovered in lump sum if amount of loan is misutilised.*—Where an enquiry conducted under rule 13 reveals that the amount of loan granted to a distressed person has not been used for the purpose for which it has been sanctioned, the competent authority shall, after giving adequate opportunity to the person concerned to explain his position, pass orders that the remaining amount of the loan with interest calculated under rule 9, and a penal interest at the rate of 5% on the loan and costs, if any, shall be recovered at once in lump sum as arrears of land revenue.

15. *Record of loanes.*—A register showing particulars of every loan granted under these rules, shall be maintained by the Tehsildar in Form II and shall be produced for inspection by the audit on demand.

FORM-I<sup>1</sup>

(See rule 4)

1. Name of applicant (s) with parentage and full address.
2. Nature of distress by which affected.
3. Extent of loss.
4. Exact location where the loss has occurred.
5. Amount of loan applied for.
6. Purpose for which the loan is required i.e. the measures which the applicant proposes to take for his rehabilitation with the help of the loan.
7. Exact location where the applicant proposes to utilise the loan on the measures stated in col. 6.
8. Details of the immovable property of the applicant(s) together with its location in revenue records, which is proposed to be mortgaged.

Signature of the Applicant(s).

Orders of the Competent Authority.

Signature with Seal of Office of the Competent Authority.

(FOR USE OF THE OFFICE OF THE TEHSILDAR AFTER THE LOAN HAS BEEN SANCTIONED)

Received payment. I/We have gone through/been explained the implications of the Himachal Pradesh Distressed Persons (Facilities for Loan) Rules, 1983 and undertake hereby to abide by these rules.

Signature (s) of the loanee(s).

I/We have gone through/been explained the implications of the above rules and after fully understanding my/our responsibilities and liabilities, undertake to pay to the Government the amount of loan together with the interest thereon, and costs, if any, in case the above loanee fails to refund the loan.

Surety No.1.....

Surety No.2.....  
(Full particulars of the sureties to be given here).

## FORM-II

(See rule 15)

1. Name of applicant(s) with parentage and address.
2. Nature of distress by which affected.
3. Extent of loss.
4. Exact location where the loss occurred.
5. Amount of loan sanctioned and reference to orders (No. and date).
6. Purpose for which loan has been sanctioned, i.e. the measures, which the applicant proposes to take for his rehabilitation with the help of the loan.
7. Details of the immovable property mortgaged with the Government in security of the loan granted to the applicant.
8. (a) Date on which the recovery of the loan is to commence in term of second proviso to rule 6.  
(b) No. of instalments fixed;  
(c) Amount of each instalment; and  
(d) Rate of interest.
9. Progress of recovery i.e. dates on which the instalments have been recovered and Challan No. and date under which the amount of instalment has been deposited.
10. The result of inspection under rule 13.
11. Orders under rule 14, if any, and the result thereof (i.e. action taken thereon).
12. Date on which the last instalment of the loan and the interest has been received.
13. Signature of the Tehsildar.

By order,  
ATTAR SINGH,  
Secretary (Revenue).

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 1984

संख्या 4-6/83-श्रम.-हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना नियम, 1972 के नियम 11 के उपनियम (2) के अन्वयन सहित हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 10 द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कथित नियमों की सूची 11 में निम्न संशोधन सहर्ष करते हैं :—

संशोधन

In Schedule II to the Himachal Pradesh Shop and Commercial Establishment Rules, 1972 after item X the following new item XI shall be inserted, namely:—

“XI All the Fair Price Shops approved/licensed by the Co-operative or Civil Supplies Department within the limit of Municipal Committee, Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh”.

Tuesday

आदेशानुसार,  
हस्ताक्षरित/-  
सचिव ।